

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2602.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 20 जनवरी, 2003/30 पौष, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2002

संख्या ई0एक्स0एन0बी(3)15/2001.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग में अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

3469-राजपत्र/2003-20-1-2003—1,482.

(3113)

मूल्य: 1 रुपया।

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग में अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त वर्ग-1 (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

- | | |
|---|--|
| 1. पद का नाम | अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त |
| 2. पदों की संख्या | 1 (एक) |
| 3. वर्गीकरण | वर्ग-1 (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) |
| 4. वेतनमान | 13500-400-15900-450-16800 रुपये |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद | चयन |
| 6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा। | लागू नहीं |
| 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं। | लागू नहीं |
| 8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं ? | आयु : लागू नहीं
शैक्षणिक अर्हताएं : लागू जैसी स्तम्भ संख्या 11 में यथा विहित की गई है। |
| 9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। |
| 10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधा होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों का प्रतिशत। | शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। |
| 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा। | संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त में से प्रोन्नति द्वारा, जो स्नातक हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से जो स्नातक हो और जिनका संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को संयुक्त रूप में 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या निरन्तर की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो जिसमें संयुक्त आबकारी |

कराधान आयुक्त के रूप में 2 वर्ष की अनिवार्य सेवा, भी सम्मिलित होगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए उन नियमों में यथार्थवाहिन सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाते के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो को ग मिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने ग्रेड/पद/कांडर में उभरे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाता है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा इन में से जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिये अयोग्य हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.—प्रन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मेड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विमिज) रूलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे ऐकममविसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विमिज) रूलज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हो।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई

निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फल-स्वरूप पारस्परिक बरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संचालना ?

जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।

लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

लागू नहीं

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा

सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-B(3)15/2001, dated 31-12-2002, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st December, 2002

No. EXN-B(3)15/2001.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Pro-

motion Rules for the post of Additional Excise and Taxation Commissioner in the Department of Excise and Taxation, Himachal Pradesh as per Annexure "A" to this Notification, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Excise and Taxation Department Additional Excise and Taxation Commissioner Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-
Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ADDITIONAL EXCISE AND TAXATION COMMISSIONER CLASS-I (GAZETTED) IN THE PAY SCALE OF RS. 13500--16800 IN THE DEPARTMENT OF EXCISE AND TAXATION, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Additional Excise & Taxation Commissioner
2. Number of posts	1 (One)
3. Classification	Class-I (Gazetted) (Non Ministerial Services)
4. Scale of pay	Rs. 13500-400-15900-450-16800.
5. Whether selection post or non-selection post?	Selection
6. Age for direct recruitment	Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees?	Age : Not applicable Educational Qualification: Yes as prescribed in Col. No. 11.
9. Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	100 % By promotion

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst Joint Excise and Taxation Commissioner who are graduate and also possess 3 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any in the grade, failing which from amongst Joint Excise and Taxation Commissioner who are graduate and also possess 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, combined as Joint Excise and Taxation Commissioner and Deputy Excise and Taxation Commissioner which shall also include essential service of two years as Joint Excise & Taxation Commissioner.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post if any prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of the seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

2. Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service as referred to above shall remain unchanged.

- | | |
|--|--|
| 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ? | As may be constituted by the Government from time to time. |
| 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. | As required under the law. |
| 14. Essential requirement for a direct recruitment. | Not applicable |
| 15. Selection for appointment to post by direct recruitment. | Not applicable |
| 16. Reservation | The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time. |

17. Departmental Examination

Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in H.P. Departmental Examination Rules, 1997.

18. Powers to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.